ORIGINAL RESEARCH PAPER

History

KEY WORDS:

बिहार के औद्योगिक विकास की समस्याएँ

डा0 मनोज कुमार

सामाजिक विकास में उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वर्तमान परिवेश में यह परिवर्तन बढ़ते उद्योगशीलता का परिचायक है। उद्योगबाद का संबंध सिर्फ सभ्यता से नहीं वल्कि हमारी शरीर रचना और मानसिक स्थिति से भी है। यंत्र निर्माण मनुष्य की शरीर रचना में ही समाया हुआ है। ईवर्ट जनरल में लेस्ली पॉल ने उद्योग को मानव स्वभाव में विद्यमान माना है। मानव समाज का विकास जंगली पपभवर सभ्य मानव अनुसार मानव सभ्यता का विकास उद्योगिक विकास के साथ माना है। औद्योगिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार किया गया है, जिनमें प्रमुख नव पाषाण सभ्यता, नगर सभ्यता, प्राचीन साम्राज्य सभ्यता, धातु एवं मुद्रण सभ्यता, प्राचीनतम राज्यों के विघटन काल को सभ्यता और प्रायोगिक विज्ञान के प्रादुर्भाव की सभ्यता है। प्रारंभिक प्रस्तुत युग के बाद प्राचीन प्रस्तर युग, फिर प्रस्तर युग, फिर तत्र ताम्र, लोह, वाष्प, विद्युत, अनु युगों में क्रमशः सभ्यता के रूप में यंत्र के साथ बदलते गए। सभ्यता के चार स्तंभ उद्योग, व्यापार कृषि एवं बौद्धिक श्रम के तीन उद्योग के ही रूपांतर माने गए हैं। उद्योग का समाज के सभी क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उद्योग के द्वारा समाज व्यवस्था रस्म रिवाज शिक्षा राजनीति अर्थ अर्थ नीति एवं नैतिकता सभी को प्रभावित किया है प्रस्तुत अध्ययन का विषय बिहार के उद्योग विकास की समस्याएं हैं, जिस पर विचार करना समीचीन होगा।

बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक पिछड़ा राज्य है एवं इसे एक बीमारू राज्य की संज्ञा दी गई है। बिहार की आर्थिक बदहाली आजादी के बाद बढ़ती गई और वर्तमान में यह चरम सीमा पर है। विकास के इस नकारात्मक उपलब्धि के परिपेक्ष्य में बिहार को विरोधाभास की भूमि कहा जाता है। मसलन प्रचुर मात्रा में संसाधनों के बावजूद भी पिछले 5 दशक में बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ता गया। आज यथार्थ यह है कि बिहार की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर गिरती जा रही है समाजिक कुशलता बढ़ रही है एवं राजनीति व्यवस्था में दरार बढ़ता जा रहा है। बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति में अच्छी नहीं है, इसकी पूरी जनसंख्या का 58 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे है और विकास के कारणों में जाए बगैर राजनीतिज्ञों ने इस बड़े दर्द का इलाज राज्य के विभाजन में खोजा और बिहार दो भागों में खंडित हो गया 15 दिसंबर 2000 स्वाभाविक है कि झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार का भौगोलिक–आर्थिक संरचना विकास में दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती बन कर आ खड़ी हुई। जिसका निराकरण असंभव तो नहीं किंतु कठिन जरूर है सबसे बड़ी चुनौती वित्तीय घाटा का है। यह घाटा इतना बड़ा है कि इस राज्य का गैर योजना मद में जरूरी खर्चा करना मुश्किल हो जाएगा। संक्षेप मैं यह कहा जा सकता है कि बिहार का वित्तीय संकट अपनी चरम सीमा पर है जिसकी भरपाई राज सुबह में बढ़ोतरी कर पाना असंभव जैसा ही है। विभाज्य का यह एक अत्यंत दुःखदाई पक्ष है कि विकास पर निवेश करने के लिए बिहार पूरी तरह लाचार हो जाएगा यह प्रमुख कारण है कि राज्य सरकार ने 1.40 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के लिए केंद्र सरकार के पास पेशकश की है।

भौगोलिक–आर्थिक संरचना के संदर्भ में बिहार की स्थिति पहले से भिन्न हो गई है। विखंडित बिहार का कुल क्षेत्रफल 92.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या का घनत्व बढ़कर 685 प्रति वर्ग किलोमीटर हो स्वाभाविक है की जनसंख्या का भार भूमि पर पहले से लगभग दूना हो गया एवं प्रति व्यक्ति भूमिका उपलब्धता भी काफी कम हो गई है बिहार पूर्ण रूप से एक अति कृषि प्रधान राज्य है कृषि राज्य की सबसे प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का केंद्र एवं इसके विकास पर ही सामाजिक आर्थिक स्थिति निर्भर करती हैं पिछले 5 दशक में संपूर्ण बिहार राज्य के कृषि का पिछड़ापन यथावत ही रहा है नव बिहार के किसी का पिछड़ापन जनसंख्या के आधार धार से ज्यादा गंभीर हो गया इसका प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट था गरीबी एवं बेरोजगारी पर पड़ेगा एवं इसके अनुपात में बढ़ोतरी ही होगी वस्तुत गरीबी एवं बेरोजगारी बिहार के दी सबसे बड़े दुश्मन होंगे।

इस पृष्ठभूमि में यह एक अहम सवाल है कि बिहार जो पहले से ही अवरूद्ध विकास की चपेट में है उसे विकास की राह पर कैसे लाया जाए मसलन विकास की रणनीति का क्या प्रारूप होना चाहिए ताकि विकास एवं सामाजिक न्याय के साथ राज्य अपने आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य को पूर्ण कर सके जहां तक विकास का प्रश्न है उसकी एक बड़ी संभावना है। खनिज को छोड़कर इस राज्य के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन एवं मानव पूंजी है यह दोनों ऐसे सकारात्मक पहलू है जिसकी मदद से नव बिहार का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। चाहे कृषि विकास का प्रश्न हो या कृषि जन उद्योग का प्रश्न है, इनके विकास की असीम संभावनाएं हैं जिसके उपयुक्त नीति निर्धारण एवं इसके समुचित करिया वन्य की मदद से हासिल किया जा सकता है किंतु, विकास की सही नीति एवं रणनीति का निर्धारण कौन करेगा निश्चित रूप से यह प्रश्न नेतृत्व से जुड़ा है। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि नेतृत्व को अपनी इस मानसिकता को बदलना होगा कि कृषि खुशहाल नहीं हो सकता है। वस्तुत बिहार के विकास का सबसे बड़ा दोष नेतृत्व हो जाता है जिसने राजनीतिक फायदा के लिए नारी का सृजन कर विकास के मार्ग को अवरुद्ध ही किया। निसंदेह भौगोलिक सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के अनुरूप रन नीतियों का निर्धारण हुआ तो शायद बिहार की अर्थव्यवस्था इतनी रोगन नहीं हुई होती गलती दोहराने का अब वक्त नहीं है बल्कि गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है जिसके प्रति नेतृत्व को गंभीर रुख अपनाना होगा।

हमारे देश में हरियाणा राज्य एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिसमें कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी विकास का एक नया आयाम स्थापित किया। नव बिहार को फिलहाल इसी मॉडल को अपनाना होगा जिस राज्य में 87 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में केवल पूंजी निवेश के माध्यम से सुधार नहीं किया जा सकता। विकास के लिए पूंजी निवेश की अनिवार्य को इनकार नहीं किया जा सकता किंतु यह भी तथ्य से परे नहीं है की बहुत बड़ी पूंजी निवेश भी यहां की पूरी श्रम शक्ति को उद्योग में नहीं लग सकता। नव बिहार मौजूद श्रम शक्ति उपजाऊ जमीन प्रचुर जल उपलब्ध पूंजी और कौशल को ध्यान में रखकर विकास का सबसे उत्तम रास्ता एवं कृषि उद्योग को प्राथमिकता देखकर कर सकते हैं। थोड़े से शब्द में यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि उपलब्ध पूंजी का बड़ा भाग कृषि क्षेत्र में निवेश होना चाहिए। पूंजी की उपलब्धता का जो प्रश्न है वह कॉफी सरल है बिहार में साथ जमा राशि का अनुपात मात्र 26% है अर्थात् बिहार में निवेश के लिए पूंजी की कमी नहीं है जरूरत इस बात की है कि बिहार का पैसा बिहार में खर्च हो इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है यह विडंबना ही है कि पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होने के बावजूद भी बिहार में मात्र 312 प्रति हेक्टर खर्च होता है जिसे आज की पूंजी उन्मुख कृषि विकास में अवरोध ही माना जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि क्षेत्र में विशेषकर ग्रामीण आधी संरचना एवं सच्चाई पर पर्याप्त पूंजी निवेश कर कृषि के विकास की वृद्धि दर को बढ़ाया जा सकता है कृषि विकास के बढ़ती गई गति से कृषि उद्योग का भी विकास होगा और इस प्रकार नव बिहार की पूरी अर्थ व्यवस्था की सार्थकता बिहार के संदर्भ में पूर्णता ग्रामीण औद्योगीकरण से जुड़ा है ग्रामीण औद्योगीकरण के माध्यम से ही ग्रामीणों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जा सकते हैं निसंदेह का अनुकूल प्रभाव ग्रामीण आवास पर होगा कृषि विकास में वृद्धि होने से कृषि से जुड़े लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी एवं कृषि क्षेत्र का ही केवल विकास नहीं होगा बल्कि इसकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार जब बिहार के व रोजगारी का प्रश्न जो प्रच्छन्न रोजगार से जुड़ा है। उसमें सकारात्मक परिवर्तन होगा एवं पूरे ग्रामीण क्षेत्र का विकास की दृष्टि से कायाकल्प हो जाएगा गरीबी और बेरोजगारी जैसे कैंसर युक्त बीमारी पर इन रणनीतियों के माध्यम से कब्जा हो जाएगा एवं नव बिहार का कृषि क्षेत्र हरियाणा की तरह विकास का एक नया आयाम स्थापित कर पाएगा। सचमुच में अगर गरीबी का प्रश्न है तो और विकास का पर्यायवाची है। वह सब कुछ मानव निर्मित जैसा लगता है मानव निर्मित इसलिए कि आज के शासक वर्ग एवं नौकरशाही व्यवस्था में विकास की सही दिशा लुप्त हो गई है ऐसा कुछ पुनः दूर आया जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिहार के विकास की परिकल्पना सपना की तरह हो जाएगा। बिहार की जरूरत है एक नए परिवेश की, एक नई विकास की एवं एक ऐसे नेतृत्व की, जो विकास के मर्म को वैज्ञानिक तरीके से समझ सके एवं उसके नेतृत्व को जो विकास के मर्म को वैज्ञानिक तरीकों से समझ सके एवं उसके अनुरूप रणनीति कार्यान्वयन कर सकें। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद नव बिहार के आर्थिक बदहाली को दूर किया जा सकता है। गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी बीमारी को दूर किया जा सके एवं जनमानस को सामाजिक आर्थिक स्थिति में गुणात्मक बुद्धि लाया जा सके। बिहार के विकास के भविष्य निरूपण की व्याख्या इन्हीं मापदंडों के आधार पर न्यायोचित है इसका सफल कार्यान्वयन विकास का सही मार्ग प्रशस्त करेगा और निसंदेह गांधी जी का वह सपना पूरा होगा जिसके उन्होंने आजादी के समय हर आंखों से आंसू पोछने का देखा था।

स्रोत एवं संदर्भ

1. चार्ल्स सिंगर संपादक ए हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी पृष्ठ– 139
2. वही पृष्ठ– 130
3. दैनिक जागरण पटना 4 अगस्त 2000 में प्रकाशित तथा पृष्ठ–15
4. पी. सी. वर्मा (2008) झारखंड में औद्योगिकरण पृष्ठ– 181
5. बिहार सरकार (1951 से 2008) सांख्यिकी पुस्तिका, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय, पटना
6. इऐस्टोव डब्लू. डब्लू. (1963) व इकोनॉमिक्स ऑफ टेंक – ऑफ इन्टू सेल्फ सस्टैण्ड ग्रोथ लन्दन, औधोगिक निर्देशिका, जन सम्पर्क निदेशालय, पटना।
7. बिहार सरकार (2001) औद्योगिक निर्देशिका जनसंपर्क निदेशालय पटना
8. डॉक्टर का कास्टा पेयर इन (1971) ए. जे फोनसेवा (इंड) चैलेन्ज ऑफ पार्टी इन इंडिया देलही।
9. वही
10. गांधीजी के अनुसार